भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2618

दिनांक 09 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मात्स्यिकी का विकास

2618. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के इरादे से मत्स्यपालन के विकास के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री आहार की आपूर्ति श्रृंखला में शीत श्रृंखला सुविध जैसी अवसंरचना की स्थापना करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में नील क्रांति योजना के लाभों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क)से(घ) मात्स्यिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और मात्स्यिकी के प्रबंधन और साक्लयवादी(होलिस्टिक) विकास के लिए मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्ष 2015-16 से नीली क्रांतिः एकीकृत विकास और मात्स्यिकी प्रबंधन पर कुल 3000 करोड़ रु. की केन्द्रीय लागत के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना(सी.एस.एस) को कार्यन्वित कर रहा है. इसके अतिरिक्त मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 7,522.48 करोड़ रु. की निधि के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ.) नामक एक समर्पित निधि बनाई है। एफ.आई.डी.एफ. का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना(सी.एस.एस.) के तहत मात्स्यिकी हेतु शीतश्रृंख्ला अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें :-

(1) शीत संयंत्रों, शीतागार, शीत संयंत्र-सह-शीतागार

(2) विद्यमान शीत संयंत्रों, शीतागार और शीत संयंत्र-सह-शीतागार का नवीकरण/आधुनिकीकरण (3) खुदरा मछली बाजार और समवर्गी अवसंरचना का विकास और (4) चल/खुदरा मछली बाजारों का निर्माण। केन्द्रीय प्रायोजित योजना(सी.एस.एस.) मत्स्य परिवहन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिनमें प्रशीतित(रेफ्रीजरेटिड) ट्रक/कंटेनर, तापरोधी(इन्सुलेटिड) ट्रक, आइस बाक्स सहित आटो रिक्शा, आइस बाक्स सहित मोटरसाइकिल, आइस बाक्स सहित बाइसाइकिल आदि शामिल हैं। एफ.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत मात्स्यिकी के लिए शीतागार(कोल्ड स्टोरेज), शीत संयंत्र, मत्स्य परिवहन और शीतश्रृंख्ला अवसंरचना आदि के विकास के लिए रियायती वित्त भी प्रदान किया जाता है।

नीली क्रांति पर बनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का मुख्य उद्देश्य देश में मछली उत्पादन को बढ़ाना है। मछली उत्पादन वर्ष 2014-15 में 10.26 मिलियन मीट्रीक टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 12.62 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है।

******